GS WORLD

एक ऐसा संस्थान जो अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है...

IAS GS WORLD PCS

Committed To Excellence

ISO 9001 Certified

PIB

PICTURE

pib

पत्र सूचना कार्यालय

PRESS INFORMATION BUREAU

भारत सरकार

DELHI CENTRE
629, Ground Floor, Main Road,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Ph.: 7042772062/63, 9868365322

ALLAHABAD CENTRE
GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Choraha, Allahabad
Ph.: 0532-2266079, 8726027579

LUCKNOW CENTRE
A-7, Sector-J, Puraniya Chauraha
Aliganj, Lucknow
Ph.: 0522-4003197, 8756450894

आयुष दवाओं की सुरक्षा निगरानी बढ़ाने के लिये नई केंद्रीय योजना

संबंधित मंत्रालय :- आयुष मंत्रालय
संबंधित मंत्री :- श्री श्रीपद येसो नाईक, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

योजना का उद्देश्य

FACT

आयुष दवाओं के फायदों के साथ ही इनके दुष्प्रभावों का लिखित रिकॉर्ड रखना और इन दवाओं के बारे में भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना है।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं की सुरक्षा निगरानी बढ़ाने के लिये एक नई केंद्रीय योजना शुरू की गयी है।

मुख्य बिंदु

- 1 नवंबर, 2017 को आयुष सचिव की अध्यक्षता में गठित स्थायी वित्त समिति ने इस योजना को मंजूरी दी थी, जिसके बाद वित्त वर्ष 2017-18 के अंत में इसे लागू करने का काम शुरू कर दिया गया।
- इसके तहत देश भर में आयुष दवाओं की निगरानी के लिये तीन स्तरीय नेटवर्क बनाने का काम किया जा रहा है।
- मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्यरत नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को आयुष दवाओं की निगरानी से जुड़ी गतिविधियों के बीच समन्वय बनाने का काम सौंपा गया है।
- योजना को लागू करने के शुरुआती स्तर पर पाँच राष्ट्रीय आयुष संस्थानों तथा 42 अन्य आयुष संस्थानों को इस काम में मदद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- इसके तहत इन संस्थानों को आयुष दवाओं का लिखित रिकॉर्ड बनाने, उसका विश्लेषण करने, दवाओं के दुष्प्रभावों का आकलन कर उनका रिकॉर्ड तैयार करने तथा आयुष दवाओं के सेवन से जुड़ी अन्य गतिविधियों का रिकॉर्ड भी रखने का काम करना है।
- मंत्रालय ने 2020 तक देश में ऐसे 100 केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है।
- आयुष दवाओं हेतु सुरक्षा नेटवर्क बनाने को सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के लिये शुरुआती तौर पर 10.60 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकार किया है।
- इसमें केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन और भारतीय फार्माकोपिया आयोग भी आयुष मंत्रालय के साथ काम कर रहा है।

रेल मंत्रालय की डिजिटल स्क्रीन सेवा

संबंधित मंत्रालय : रेल मंत्रालय, संबंधित – पीयूष गोयल

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में रेलवे मंत्रालय ने भारतीय रेल के गौरवशाली अतीत से लोगों को रूबरू कराने के लिये देश के 22 रेलवे स्टेशनों पर इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डिजिटल स्क्रीन का संचालन शुरु कर दिया है।
- साथ ही इसमें विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रेलवे की विरासत पर क्यूआर कोड आधारित पोस्टर भी लगाए गए हैं।
- यह पहल रेलवे स्टेशनों पर क्विक रेसपांस (क्यूआर) कोड आधारित डिजिटल संग्रहालय बनाए जाने के प्रधानमंत्री के विजन पर आधारित है।

उद्देश्य

- भारतीय रेल की विरासत के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिये रेल मंत्रालय ने डिजिटल स्क्रीन सेवा लॉन्च की है।

विशेषताएं

- यह एक अभिनव और कम खर्चीला प्रयोग है।
- प्रायोगिक स्तर पर शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य लोगों को एक से दो मिनट की अवधि में लघु फिल्मों के जरिये भारतीय रेल की समृद्ध विरासत की जानकारी देना है।
- ये लघु फिल्में रेलवे स्टेशनों के प्रवेश द्वारों और यात्रियों के बैठने के स्थानों पर लगाए गए डिजिटल एलईडी स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी।
- इस तरह के डिजिटल स्क्रीन फिलहाल नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, हावड़ा, सियाल्दाह, जयपुर, आगरा छावनी, कोयंबटूर, लखनऊ, वाराणसी और अन्य रेलवे स्टेशनों पर लगाए गए हैं।
- इसके अलावा रेलवे की विरासत को दर्शाने वाले क्यूआर कोड आधारित पोस्टर भी इन रेलवे स्टेशनों पर लगाए गए हैं।
- यात्री इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल फोन पर स्कैन करके रेलवे की विरासत से जुड़ी वीडियो फिल्में देख सकते हैं।
- नई दिल्ली और हावड़ा स्टेशन पर ऐसे पोस्टरों और डिजिटल स्क्रीन के लिये अलग से एक डिजिटल वॉल बनाया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी 2018 में हालिया प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

संबंधित मंत्रालय :- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
संबंधित मंत्री :- श्रीमती हरसिमरत कौर बादल

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में हालिया प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (iCRAFPT) 2018 की शुरुआत 17 अगस्त को शुरू हुआ।
- यह तमिलनाडु के तंजावुर के भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान में शुरू हुआ है।
- इसकी थीम ¶Doubling farmers income through food processing है।

मुख्य बिंदु

- 3 दिवसीय सम्मेलन खाद्य शोध के सबसे आगे अंतर्राष्ट्रीय और अंत:विषय विनिमय के लिए मूल्यवान और महत्वपूर्ण मंच है।
- इसमें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध वक्ताओं खाद्य शोध इंजीनियरिंग और इसके औद्योगिक अनुप्रयोगों, खाद्य उत्पाद विकास, खाद्य जैव प्रौद्योगिकी, नैनो खाद्य पदार्थों में प्रगति के क्षेत्रों में अपने शोध अनुभव साझा करेंगे।
- इस सम्मेलन में खाद्य प्रसंस्करण से सम्बंधित 8 विविध तकनीकी सत्र आयोजित किये गए।
- इस सम्मेलन में 9 विदेशी प्रवक्ता, 77 भारतीय प्रवक्ता, 18 औद्योगिक विचार-विमर्श, 30 श्रेणी भाषण तथा 2 पैनल डिस्कशन ने हिस्सा लिया।

भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान

- यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MOFPI) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम कर रहे प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है।
- इसका मुख्यालय तंजावुर में स्थित है।
- यह संस्थान खाद्य प्रसंस्करण के बारे में शोध व शिक्षा का कार्य करता है।
- खाद्य प्रसंस्करण सम्बन्धी व्यापार में किसानों, उद्यमियों तथा युवाओं की सहायता करता है।

नदी संयोजन के लिए गठित विशेष समिति की 15वीं बैठक

संबंधित मंत्रालय :- जल संसाधन मंत्रालय
संबंधित मंत्री :- श्री नितिन गडकरी

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में नदी संयोजन के लिए गठित विशेष समिति की 15वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई।
- बैठक में नदियों के संयोजन के विषय में संबंधित राज्यों के बीच सहमति विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- इससे पानी के बिना उपयोग में आये हुए समुद्र में जाने के पहले पानी का उन क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकेगा, जहाँ इसकी आवश्यकता है।
- राज्यों से आह्वाहन किया गया कि परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित करने के लिए वे सक्रिय परामर्श द्वारा समस्याओं की पहचान और उनपर चर्चा करें।

अब तक की प्रगति

- पाँच नदी संयोजन परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए कदम उठाते हुए संबंधित राज्य सरकारों से विमर्श कर इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समझौता पत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- ये पाँच परियोजनाएँ है- केन बेतवा परियोजना, दमनगंगा-पिंजाल परियोजना, पर तापी-नर्मदा परियोजना, गोदावरी-कावेरी परियोजना एवं पार्वती काली सिन्धु-चंबल परियोजना

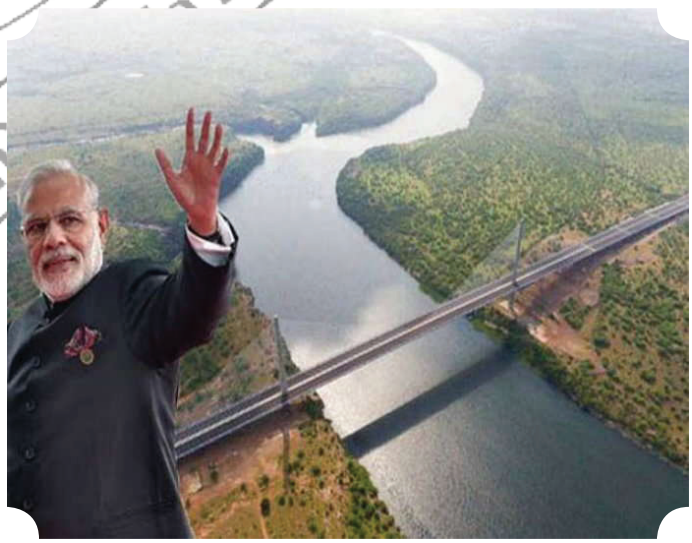

नदी संयोजन के लाभ

- इससे सुखाड़-उन्मुख तथा जल की कमी वाले क्षेत्रों को पानी मिलेगा और फसल की पैदावार बढ़ेगी।
- हिमालय से निकलने वाली नदियों में उपलब्ध् अतिरिक्त पानी प्रायद्वीपीय भारत की ओर स्थानांतरित हो पायेगी।
- गंगा घाटी और ब्रह्मपुत्रा घाटी में लगभग हर वर्ष बाढ़ आती है। इसके माध्यम से इन घाटियों में बह रही नदियों के जल की दिशा दूसरे कम पानी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करने से बाढ़ की समस्या का समाधान संभव है।
- नदियों को जोड़ने से घरेलू जलमार्ग के रूप में इनका प्रयोग हो सकता है। ऐसा करने से सार्वजनिक यातायात और माल ढुलाई पहले से तीव्र हो जायेगी।
- नदी संयोजन से बनाई गई नई नहरों के आस-पास रहने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा और मछली पालन का काम भी बड़े पैमाने पर हो सकेगा।

नदी संयोजना के संभावित दुष्प्रभाव

- इसके कारण नहरें और जलाशय बनाए जायेंगे जिनके चलते बहुत बड़े पैमाने पर जंगलों की सफाई की जायेगी। इसका प्रभाव वर्षा पर पड़ेगा और अंततः संपूर्ण जीवन चक्र प्रभावित हो जायेगा।
- नदियों को जोड़ा भी जाए तो ऐसा अनुमान है कि 100 वर्ष के अंदर ये अपना रास्ता और दिशा फिर से बदल सकते हैं।
- नदियों के संयोजना से एक हानि यह है कि समुद्र में प्रवेश करने वाले मीठे जल की मात्रा घट जाएगी जिसके कारण सामुद्रिक जीवन तंत्र पर गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा।
- बहुत सारी नहरों और जलाशयों के निर्माण से लोगों को विस्थापित करना आवश्यक हो जायेगा और इनका पुनर्वास करना एक समस्या हो जाएगी।
- नदी संयोजना के परियोजनाओं पर संभावित खर्च बहुत विशाल होगा और इसके लिए सरकार को विदेशी स्रोतों से ऋण लेना होगा।

तिरुवनंतपुरम में होगी चक्रवात चेतावनी केंद्र की स्थापना

संबंधित मंत्रालय :- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
संबंधित मंत्री :- डॉ हर्षवर्धन

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में गंभीर मौसमीय घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय विज्ञान मंत्रालय ने तिरुवनंतपुरम में एक चक्रवात चेतावनी केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

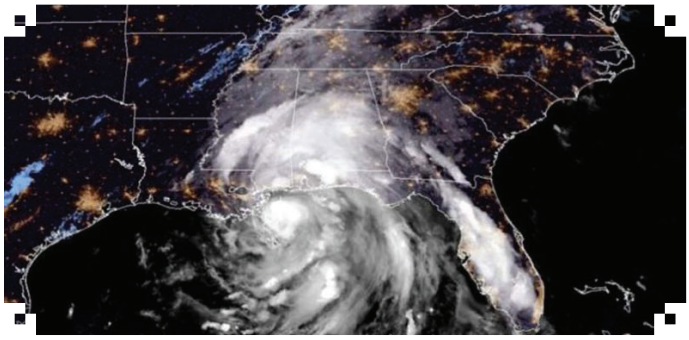

- इसे मंत्रालय द्वारा केरल और कर्नाटक के समुद्रों तटों पर हाल के दिनों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और उनसे होने वाली गंभीर मौसमीय घटनाओं को देखते हुए अगले एक महीने के भीतर स्थापित किया जाएगा।
- वर्तमान में, भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के पास केवल चेन्नई, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, अहमदाबाद और मुंबई में चक्रवात चेतावनी केंद्र हैं।

चक्रवात चेतावनी केंद्र

- केंद्र सरकार केरल और कर्नाटक की जरूरतों को पूरा करेगी और सभी राज्यों को मौसम की चेतावनियों तथा तटीय बुलेटिन (मछुआरों आदि के लिए) जारी करने के लिए पूर्वानुमान उपकरण सहित सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएगी।
- इस कदम से भारतीय मौसम विभाग के केरल में स्थित वर्तमान पूर्वानुमान गतिविधियों को और मजबूती मिलेगी।
- मंत्रालय 2019 के अंत तक मैंगलोर में भी एक और सी-बैंड डॉप्लर मौसम रडार स्थापित करने की योजना बना रहा है, जो केरल के उत्तरी हिस्सों को कवर करेगा।
- वर्तमान में केरल में दो डॉप्लर मौसम राडार हैं जिनमें एक कोच्चि और दूसरा तिरुवनंतपुरम में स्थित है।
- इन 3 रडारों के माध्यम से पूरे राज्य में बारिश और गंभीर मौसम की घटनाओं की निगरानी रखी जाएगी और लोगों को मौसम संबंधित चेतावनी पहले से ही जारी की जाएगी।
- आईएमडी ने अब तक कई नए प्रारूप विकसित किए हैं।
- विभाग सभी राज्यों के राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों के साथ अगले महीने एक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने की योजना बना रहा है।
- प्रभावी निर्णय लेने के लिए इस कार्यशाला में अधिकारियों को नए उपकरणों तथा उनके उपयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी।

TRIFED (ट्राइफेड)

संबंधित मंत्रालय :- जनजातीय कार्य मंत्रालय
संबंधित मंत्री :- श्री जुएल ओराम

चर्चा में क्यों?

- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (TRIFED) ने चालू वित्त वर्ष के दौरान जनजातीय उत्पादों की रिकॉर्ड खरीददारी की है।
- पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में खरीद में 511% की वृद्धि हुई है।
- अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने जनजातीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के सरकार के प्रयासों के तहत करीब एक हजार पंखे ट्राइफेड से लिए थे।
- ये एजेंसी जनजातीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है।

Tribal Co-operative Marketing Federation of India (TRIFED)

ट्राईफेड
TRIFED

क्या है?

- यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम कर रहे एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है।
- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्राईफेड) को 6 अगस्त, 1987 को स्थापित किया गया।
- इसे बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1984 के अंतर्गत पंजीकरण किया गया है (जो अब बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 है)।
- इसने भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में वर्ष 1988 से कार्य करना प्रारंभ किया (जो अब भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय है)।
- ट्राईफेड का पंजीकृत मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है और देश के विभिन्न स्थानों पर 13 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

उद्देश्य और कार्य

- जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास के जरिए जनजातीय लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना है।
- यह जनजातीय लोगों के हितों को उनके लघु वन उत्पादन और आदिवासी कला और हस्तशिल्प उत्पादों के लिए बेहतर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करके सेवा प्रदान करता है।
- यह छोटे वन उत्पादन के विपणन को विकसित करने के लिए कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण में भी शामिल है।
- इसके दृष्टिकोण में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, ब्रांड निर्माण और सतत आधार पर विपणन के अवसर बनाने के अवसरों के लिए विपणन संभावनाओं की खोज करना शामिल है।

भारतीय हिमालयन क्षेत्र में निरंतर विकास पर पांच रिपोर्टों की शुरूआत

संबंधित मंत्रालय :- नीति आयोग
संबंधित मंत्री :- नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष
डॉ. राजीव कुमार (उपाध्यक्ष)
श्री अमिताभ कांत (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में नीति आयोग ने भारतीय हिमालयन क्षेत्र में निरंतर विकास पर विषय संबंधी पांच रिपोर्टों की शुरूआत की है।
- विषय संबंधी पांच क्षेत्रों में कार्य करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से नीति आयोग ने जून, 2017 में हिमालय की विशिष्टता और निरंतर विकास की चुनौतियों को समझते हुए पांच कार्य दलों का गठन किया था।
- भारत के हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में 2025 तक पर्यटकों की संख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया गया है।

शामिल किये गये क्षेत्र-

- हिमालय में झरनों का आविष्कार और जल सुरक्षा के लिए फिर से चालू करना
- भारतीय हिमालय क्षेत्र में निरंतर पर्यटन
- कृषि के लिए परिवर्तनीय दृष्टिकोण
- हिमालय में कौशल और उद्यमिता परिदृश्य को मजबूत बनाना
- बेहतर फैसले करने के लिए डेटा या जानकारी

चिंताएं-

- रिपोर्ट के अनुसार, करीब 30 प्रतिशत झरने सूख रहे हैं और 50 प्रतिशत में बहाव कम हुआ है।
- ठोस कचरा, पानी, यातायात, जैव-सांस्कृतिक विविधता के नुकसान संबंधी बड़ी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं।
- कौशल और उद्यमिता को मजबूती प्रदान करने के लिए पहचाने गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, पहाड़ों से लाभ वाले क्षेत्रों, प्रशिक्षकों के लिए निवेश, उद्योग साझेदारी में प्रशिक्षण केन्द्र पर ध्यान देने की जरूरत है।

राष्ट्रपति ने 'अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2018' का उद्घाटन किया

संबंधित मंत्रालय :- पर्यटन मंत्रालय
संबंधित मंत्री :- श्री के.जे. अल्फोंस, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में प्रमुख बौद्ध विरासत और तीर्थ स्थलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम ने पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से औरंगाबाद में 6वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, 2018 का आयोजन किया।
- *इस बार का विषय – 'बुद्ध पाथ द लिविंग हेरिटेज'*

- इस सम्मेलन का आयोजन में बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने भी साथ दिया।
- इस बार अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का सहयोगी देश जापान था।
- इसका आयोजन नई दिल्ली और अजंता (महाराष्ट्र) में किया जा रहा है, बाद में राजगीर, नालंदा, बोधगया (बिहार) और सारनाथ (उत्तर प्रदेश) की यात्रा भी की जाएगी।
- इस सम्मेलन में 29 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- इसमें बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार और श्रीलंका के मंत्रीस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुए।

बौद्ध सम्मेलन के उद्देश्य

- बौद्ध धर्म वाले देशों से मैत्री संबंध स्थापित करना
- बौद्ध धार्मिक स्थलों में पर्यटन को बढ़ावा देना
- भारत में बौद्ध धरोहर को प्रदर्शित करना

अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन

- इसका आयोजन केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रत्येक दो वर्ष बाद किया जाता है।
- फरवरी 2004 में इसका आयोजन नई दिल्ली और बोधगया में किया गया था।
- फरवरी, 2010 में इसका आयोजन नालंदा और बोधगया में किया गया था।
- सितम्बर, 2012 व 2014 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन का आयोजन वाराणसी और बोधगया में किया गया था।
- अक्टूबर, 2016 में इसका आयोजन सारनाथ/वाराणसी और बोधगया में किया गया था।

सार्वजनिक उपक्रमों के लिए खेल नीति जारी

संबंधित मंत्रालय - इस्पात मंत्रालय
संबंधित मंत्री - श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केन्द्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए खेल नीति जारी की।
- इस नीति के जरिए इस्पात मंत्रालय के अधीन आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा सकेगा।
- चौधरी बीरेंद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा कि खेल देश के आर्थिक विकास और ताकत की पहचान होते हैं।
- मंत्रालय के अधीन आने वाले सार्वजनिक उपक्रम भविष्य में ओलम्पिक खेलों के लिए पदक विजेता तैयार करेंगे।

मुख्य तथ्य

- नई नीति के अनुरूप ये उपक्रम खेल प्रतिभाओं को ढूंढकर उन्हें ढांचागत और वित्तीय मदद तथा प्रशिक्षण और कोचिंग की सुविधा देंगे।
- नई नीति के तहत मंत्रालय के सभी सार्वजनिक उपक्रम एक शीर्ष खेल निकाय का गठन करेंगे, जो राष्ट्रीय स्तर के खेल संघों और परिसंघों, भारतीय ओलम्पिक संघ और पैराओलम्पिक संघ और परिसंघों के साथ संबद्ध होंगे।
- महारत्न और नवरत्न का दर्जा पाए सार्वजनिक उपक्रम कम से कम एक खेल के लिए अपने यहां खेल अकादमी स्थापित करेंगे और वहां खिलाड़ियों के लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।
- इस्पात मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम खेल गतिविधियों के लिए अब अपनी वित्तीय स्थिति के अनुरूप अलग से बजट का प्रावधान करेंगे। यह बजट उनके सामाजिक उत्तरदायित्व वाले बजट से अलग होगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने तथा निःशक्तजनों के लिए खेल गतिविधियां शुरू करने पर सार्वजनिक उपक्रमों का विशेष जोर रहेगा।
- वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को प्रायोजित करने का भी काम करेंगे।

निर्वाचन आयोग की राजनैतिक दलों के साथ बैठक

संबंधित आयोग – भारतीय निर्वाचन आयोग
संबंधित आयुक्त – श्री ओम प्रकाश रावत

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित एक बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों और राज्य के राजनैतिक दलों ने हिस्सा लिया।

बैठक का उद्देश्य

- निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करना ताकि महत्त्वपूर्ण विषयों पर उनके विचार प्राप्त हो सकें।
- निर्वाचन आयोग हमेशा से वर्तमान निर्वाचन प्रणाली और अपनी कार्य पद्धति में सुधार करके देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाने के कार्य में संलग्न रहता है।
- इस बैठक में पंजीकृत सभी 7 राष्ट्रीय राजनैतिक दलों और 34 राज्य स्तरीय पार्टियों ने हिस्सा लिया।

कार्य सूची में शामिल विषय

- आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदाता सूचियों की विशुद्धता, पारदर्शिता में सुधार करना।
- महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उपाय पर विचार करना।
- चुनाव खर्च पर नियंत्रण करने, विधान परिषद के चुनावों के खर्च की सीमा तय करने और राजनैतिक दलों का खर्च सीमित करने के विषय पर विचार-विमर्श किया गया।
- इसके अलावा वार्षिक लेखा रिपोर्ट, चुनाव खर्च रिपोर्ट समय पर देने के उपाय लागू करने के बारे में विचार-विमर्श भी इस कार्य सूची का हिस्सा था।

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुच्छेद 126(1)(बी) के दायरे में चुनाव प्रचार बंद होने की अवधि में प्रिंट मीडिया को शामिल करने सहित और मतदान समाप्त होने से पहले अंतिम 48 घंटों के दौरान सोशल मीडिया पर पार्टी/उम्मीदवार की चुनावी संभावनाओं को बढ़ाने अथवा पूर्वाग्रह के लिये ऑनलाइन प्रचार के मुद्दे पर भी बैठक में विचार किया गया।

चुनाव कराने के संबंध में महत्त्वपूर्ण विचार

- प्रवासियों और अनुपस्थित मतदाताओं के लिये मतदान के वैकल्पिक तरीके।

इलेक्ट्रोनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बेलोट सिस्टम (ईटीबीपीएस)-

- ईटीबीपीएस योजना के संचालन के संबंध में राजनैतिक दलों के विचार और फीडबैक।
- दिव्यांग मतदाताओं की मतदान में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के संबंध में राजनैतिक दलों के विचार और फीडबैक पर भी बैठक में विचार किया गया।
- मतदान में भागीदारी सहित पहुँच बढ़ाने और व्यापक आधार को प्रोत्साहित करने के आयोग के प्रयासों के संबंध में राजनैतिक दलों के विचार एवं फीडबैक आमंत्रित किये गए हैं।

उत्तराखंड की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना

संबंधित मंत्रालय - जल संसाधन मंत्रालय
संबंधित मंत्री - श्री नितिन गडकरी

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने देहरादून के नजदीक यमुना पर लखवाड़ बहुउद्देश्यीय परियोजना के निर्माण के लिए 6 राज्यों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- इन 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली शामिल है।
- इसका उद्देश्य पानी के संकट से निपटना है।
- वर्ष 1992 में परियोजना का काम रूक गया था।

परियोजना के बारे में

- कुल परियोजना 3,966.51 करोड़ रुपये की है।
- परियोजना की 90% लागत केंद्र द्वारा वित्त पोषित की जाएगी जबकि शेष राशि का भुगतान छह राज्यों द्वारा किया जाएगा।
- इनमें से 1388.28 करोड़ रुपए उत्तराखंड सरकार द्वारा दिए जाएंगे।
- इससे इस प्रकार जनवरी और जून के बीच जल संकट से निपटने के लिए ऊपरी यमुना बेसिन में भंडारण की सुविधा बनाने के मानसून प्रवाह का उपयोग होगा।

लाभ

- परियोजना से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। परियोजना निर्माण का काम उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड करेगा।
- समझौते के तहत, 204-मीटर ऊंची परियोजना का 330,66 लाख घन मीटर (एमसीएम) की भंडारण क्षमता के साथ उत्तराखंड के लोहारी गांव के निकट निर्माण किया जाएगा।
- इसके निर्माण से यमुना की जल भंडारण क्षमता में 65 फीसदी बढ़ोतरी हो जाएगी।
- इससे 33,780 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी।

गगनयान मिशन-2022

संबंधित विभाग - अंतरिक्ष विभाग
संबंधित कार्यकारी अध्यक्ष - ए.एस. किरण कुमार

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में प्रधान मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर 370 साल पुराने लालकिले से दिए गए अपने संबोधन में ऐलान किया कि 2022 तक गगनयान लेकर कोई हिंदुस्तानी अंतरिक्ष में जाएगा।
- इस घोषणा पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
- अब भारत अंतरिक्ष में इंसान भेजने वाला चौथा राष्ट्र बन जाएगा।
- साल 2022 भारतीय स्वतंत्रता का 75वां साल होगा।
- इसके लिए करीब 9 हजार करोड़ रुपये बजट रखा गया है।
- गगनयान को लॉन्च करने के लिए जीएसएलवी एमके-3 लॉन्च व्हिकल का उपयोग किया जाएगा जो इस मिशन के लिए आवश्यक पेलोड क्षमता से परिपूर्ण है।

मिशन के उद्देश्य

- देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर में वृद्धि
- एक राष्ट्रीय परियोजना जिसमें कई संस्थान, अकादमिक और उद्योग शामिल हैं
- औद्योगिक विकास में सुधार
- प्रेरणादायक युवा
- सामाजिक लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का विकास
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सुधार

क्या होगी चुनौतियाँ?

- लक्ष्य हासिल करने के लिए तकनीक को बेहतर करना होगा।
- समय बहुत कम है।
- अंतरिक्ष यात्रा (ऐस्ट्रोनॉट) के लिए ट्रेनिंग और एक बड़ा रॉकेट दो प्रमुख चुनौतियां हैं।

पहला विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन 2018

संबंधित आयोग :- नीति आयोग
संबंधित मंत्री :- नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष (चेयरपर्सन)
डॉ. राजीव कुमार उपाध्यक्ष
श्री अमिताभ कांत (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने 31 अगस्त से 06 सितंबर, 2018 तक चलने वाले "मोबिलिटी-वीक" के मद्देनजर आयोजनों की एक श्रृंखला का अनावरण किया है।
- मूव भारत के प्रथम विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन-2018 के संबंध में है, जिसका आयोजन विज्ञान भवन में 07 और 08 सितंबर, 2018 को होगा।
- इसके जरीये भावी संभावनाओं तथा अवसरों एवं चुनौतियों से निपटने के लिए देश की तैयारी का जायजा लिया जाएगा।

क्या है?

- इसके तहत 31 अगस्त से 06 सितंबर, 2018 तक 17 आयोजन होंगे।
- इन आयोजनों में मोबिलिटी क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा का अवसर मिलेगा।
- प्रतिभागियों में विश्व और भारत के मोबिलिटी क्षेत्र के दिग्गज शामिल हैं।
- इनमें ओईएम, बैटरी निर्माता, चार्जिंग अवसंरचना प्रदाता, प्रौद्योगिकी सॉल्यूशन प्रदाता, भारत सरकार और विदेशों के प्रतिनिधि, विभिन्न अंतर-सरकारी संगठन, अकादमिक जगत और पॉलिसी थिंक-टैंक शामिल हैं।
- इसके तहत सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में सार्वजनिक यातायात, साझा मोबिलिटी और संपर्कता के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी।
- इसके अलावा नीति आयोग के साथ मिलकर भारतीय रेल एक संगोष्ठी का आयोजन करेगी, जिसका विषय 'भारतीय रेल में ई-मोबिलिटी' है।

- इसका उद्देश्य परियोजना विकास कर्ताओं और अन्य हितधारकों को एक साझा मंच पर लाना है, ताकि भारतीय रेल को प्रभावशाली, हरित और सर्व सुलभ यातायात बनाया जा सके।

आवश्यकता क्यों पड़ी?

- प्रौद्योगिकी लागत और व्यापार आधारित इनोवेशन के मद्देनजर दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत वाहनों की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है।
- इस पृष्ठभूमि में विभिन्न मंत्रालयों और उद्योग साझेदारों के सहयोग से नीति आयोग मूव : विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
- इसके तीन प्रमुख बिंदु- सम्मेलन, डिजिटल प्रदर्शनी, विशेष आयोजन

लाभ

- इससे वाहनों के विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा और रोजगार विकास के लिए सरकार के उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलेगी तथा स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत के कदम तेजी से बढ़ेंगे।
- यह अपने तरह का यह पहला शिखर सम्मेलन है, जिसमें पूरे विश्व से 1200 प्रतिभागियों के शामिल होने की आशा है

अनुचित तरीके से मुकदमा चलाने पर रिपोर्ट जारी

संबंधित आयोग :- कानून एवं न्याय
संबंधित मंत्री :- श्री रविशंकर प्रसाद

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में विधि आयोग ने "अनुचित तरीके से मुकदमा चलाने (न्याय की हत्या): कानूनी उपाय" नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।
- दिल्ली हाईकोर्ट ने बबलू चौहान बनाम दिल्ली सरकार मामले में निर्देश देते हुए निर्दोष व्यक्तियों पर अनुचित मुकदमा चलाने जैसी स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी।

प्रमुख बिंदु

- अदालत ने अनुचित तरीके से मुकदमे के शिकार लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए एक कानूनी रूपरेखा तैयार करने की तत्काल आवश्यकता बताई थी और विधि आयोग से कहा था कि वह इस मुद्दे की विस्तृत जांच का काम हाथ में ले और सरकार को अपनी सिफारिशें दें।
- नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम भी 'न्याय की हत्या' के शिकार लोगों को मुआवजा देने के लिये सदस्य राष्ट्रों के दायित्वों की बात करता है।

संबंधित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. हाल ही में जारी आयुष दवाओं की सुरक्षा निगरानी बढ़ाने हेतु नई केन्द्रीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस केन्द्रीय योजना को आयुष मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है।
2. इसका उद्देश्य आयुष दवाओं के फायदों के साथ ही इसके दुष्प्रभावों का लिखित रिकॉर्ड रखना और इन दवाओं के बारे में भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

2. हाल ही में चर्चित 'डिजिटल स्क्रीन सेवा' के सम्बंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है?

(a) यह सेवा रेल मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ की गयी है।
(b) इसका उद्देश्य भारतीय रेल की विरासत के प्रति लोगों को जागरूक बनाना हैं।
(c) इसके माध्यम से लघु फिल्में रेलवे स्टेशनों के प्रवेश द्वारों और यात्रियों के बैठने के स्थान पर लगायी गयी एलईडी स्क्रीन पर दिखायी जायेगी।
(d) उपर्युक्त सभी

3. निम्नलिखित कथनों में से कौन-से कथन सत्य हैं?

1. खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में हाल में हुए प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तंजावुर (तमिलनाडु) में सम्पन्न हुआ।
2. भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, खाद्य प्रसंस्करण के बारे में शोध व शिक्षा का कार्य करता है।
3. खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में हालिया प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम ''खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करना'' है।

नीचे दिये गये कूट के प्रयोग से सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

4. निम्नलिखित में से कौन-सी नदी संयोजन परियोजना को क्रियान्वयन के लिये अंतिम रूप दिया जा रहा है?

(a) केन-बेतवा परियोजना
(b) दमन गंगा-पिंजाल परियोजना
(c) पार्वती काली सिंधु-चम्बल परियोजना
(d) उपर्युक्त सभी

5. निम्नलिखित में से चक्रवात चेतावनी केन्द्र कहाँ स्थ. ापित करने का प्रस्ताव रखा गया है?

(a) दिल्ली
(b) तिरुवंतपुरम
(c) चेन्नई
(d) पुलीकट

6. 'ट्राइफेड' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह जनजाति कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य कर रहे राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है।
2. इसका उद्देश्य जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास के माध्यम से जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास करना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

7. हाल ही में निम्नलिखित में से किसने भारतीय हिमालयन क्षेत्र में निरंतर विकास पर विषय से सम्बंधित रिपोर्टों की शुरूआत की है?

(a) नीति आयोग
(b) मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(c) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(d) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

8. अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन-2018 के सम्बंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम ने औरंगाबाद में किया था।
2. अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक दो वर्ष बाद केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

9. **केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिये जारी खेल नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. इस नीति के माध्यम से इस्पात मंत्रालय के अधीन आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों में खेलों को बढ़ावा दिया जायेगा।
2. इस नई नीति के अनुरूप यह सार्वजनिक उपक्रम खेल प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें ढ़ाँचागत और वित्तीय सहायता तथा प्रशिक्षण और कोचिंग की सुविधा दी जायेगी।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

10. **हाल ही में निर्वाचन आयोग की राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक के सम्बंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं?**

1. इस बैठक का उद्देश्य राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श करके महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार प्राप्त करना है।
2. इस बैठक का आयोजन भारतीय निर्वाचन आयोग ने किया था।
3. इस बैठक में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उपाय पर विचार करने जैसे विषय शामिल नहीं थे।

नीचे दिये गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

11. **लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है?**

(a) यह परियोजना यमुना नदी पर स्थापित की जायेगी।
(b) इसमें केवल उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश शामिल हैं।
(c) इस परियोजना का उद्देश्य पानी के संकट से निपटना है।
(d) इस परियोजना का निर्माण कार्य 1992 में रूक गया था जो पुनः प्रारंभ किया जायेगा।

12. **'गगनयान मिशन-2022' के सम्बंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है?**

(a) इसका सम्बंध भारत द्वारा अंतरिक्ष में इंसान भेजने से है।
(b) गगनयान को लाँच करने के लिये जीएसएलवी एमके-3 प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया जायेगा।
(c) यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा संचालित किया जायेगा।
(d) उपर्युक्त सभी

13. **विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन-2018 के सम्बंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. इसके माध्यम से भावी संभावनाओं तथा अवसरों एवं चुनौतियों से निपटने के लिये देश की तैयारी का जायजा लिया जायगा।
2. इस सम्मेलन के आयोजन में मोबिलिटी क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा का अवसर मिलेगा।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

14. **हाल ही में विधि आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के सम्बंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. इस आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट का शीर्षक ''अनुचित तरीके से मुकद्मा चलाने (न्याय की हत्या) कानूनी उपाय'' है।
2. इस रिपोर्ट में आयोग ने अनुचित तरीके से मुकद्मा चलाने के मामले के निपटारे के लिये विशेष कानूनी प्रावधान की सिफारिश की है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

15. **'राजभाषा विभाग' के सम्बंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विभाग है।
2. इसने 'प्रवाह' नामक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का प्रारंभ किया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2